RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : गुरुवार 21 जुलाई 2022 वर्ष 04 अंक 83 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
R
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

'संजय राउत ने ही शिवसेना को तोड़ा है' ...!

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान

मुंबई : केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शिवसेना में फूट के लिए शिवसेना सांसद संजय राउत को जिम्मेदार ठहराया है. बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत में रामदास अठावले ने कहा, 'मुझे लगता है कि संजय राउत ने ही शिवसेना को तोड़ा है, संजय राउत के कहने पर ही उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस-ठउढ के साथ जाने का निर्णय लिया था.'

शिंदे गुट की बगावत के बाद अल्पमत में आ गई थी सरकार

बता दें कि कुछ दिनों पहले शिवसेना में अंदरूनी कलह के बाद पार्टी दो धड़ों में बंट गई थी, जिसमें एक धड़ा सीएठ ठाकरे और दूसरा धड़ा एकनाथ शिंदे के समर्थन में था. शिंदे को समर्थन देने के बाद शिवसेना की सरकार अल्पमत में आ गई और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा. अब तक उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे थे, लेकिन अब महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार है जो खुद को असली शिवसैनिक मानते हैं.

इस बगावत के पीछे एकनाथ शिंदे का कहना था कि बाला साहेब ठाकरे कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करना नहीं चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनके उसूलों के खिलाफ जाकर सरकार बनाने में कांग्रेस का समर्थन लिया, जो कि एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आया. वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि उद्धव सरकार में संजय राउत को ज्यादा वरीयता दी जा रही थी, जिससे एकनाथ शिंदे नाराज थे.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में OBC कोटे के साथ चुनाव की दी अनुमति- फडणवीस

तत्काल चुनाव की नई तारीखों की घोषणा नहीं करने का अनुरोध

महाराष्ट्र में अब ओबीसी कोटे के साथ स्थानीय निकाय चुनाव हो सकते हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को यह बात कही। भाजपा नेता ने संवाददाताओं से कहा कि हालांकि प्रदेश सरकार ने राज्य चुनाव आयोग से स्थानीय निकायों के लिए तत्काल चुनाव नहीं कराने का अनुरोध किया है क्योंकि महाराष्ट्र के कई हिस्से भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं।

मुंबई : इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए उनकी आबादी के बारे में अनुभवजन्य आकंड़ों की कमी के चलते अलग कोटा रखा था।

राज्य चुनाव आयोग से चुनाव की नई तारीखों की घोषणा न करने का अनुरोध

फडणनवीस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। उसने आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ओबीसी आरक्षण को आवंटित करने की अनुमति दी है। लेकिन सरकार ने राज्य के चुनाव आयोग से तत्काल चुनाव की नई तारीखों की घोषणा नहीं करने का अनुरोध किया है क्योंकि कई इलाके भारी बारिश से बुरी तरह प्रभावित हैं और स्थिति को प्राथमिकता के आधार पर संभालने की जरूरत है।

पिछले महीने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पार्टी द्वारा शिवसेना का बागी नेता एकनाथ शिंदे का समर्थन करने के बाद वह उप मुख्यमंत्री बने। इससे पहले फडणवीस ने पिछली महा विकास अघाड़ी सरकार पर इस मुद्दे पर केंद्र पर उंगली उठाकर समय बर्बाद करने का आरोप लगाया।

मैं अपना आधिकारिक काम साथ लेकर चलता हूं : सीएम शिंदे

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह हर समय मंत्रालय में नहीं बैठते हैं, क्योंकि जहां भी जाते हैं, अपना आधिकारिक काम लेकर चलते हैं। वहीं पर फाइलों पर हस्ताक्षर करते हैं। दरअसल, एक दिन पहले विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया था कि मंत्रालय में कोई काम नहीं हो रहा है। ठाणे जिले में आयोजित रैली में उन्होंने इस आरोप पर जवाब दिया।

सरकार ने बैन किए ७८ यूट्यूब चैनल

दशहत फैलाने का दिया हवाला

मुंबई : हाल ही में भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्षी सांसदों की जुबान बंद करने की कोशिश में जुट गई थी। इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें संसद में उन शब्दों पर पाबंदी लगाने की बात कही गई थी, जिनका भाजपा के लोग कभी बेझिझक उपयोग करते थे। पहले सांसदों की जुबान बंद की गई और अब अभिव्यक्ति की आजादी भी गुलामी की ओर जा रही है। दरअसल अब सरकार ने ७८ यूट्यूब चैनल पर बैन लगा दिया है। ये वो यूट्यूब चैनल हैं, जो केंद्र के खिलाफ खबरें चलाते थे। ये कार्रवाई आईटी एक्ट २००० की धारा ६९ए के उल्लंघन के आरोप में की गई है। सूचना प्रसारण मंत्री ने मंगलवार को ७८ यूट्यूब न्यूज चैनल और उनके सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सरकार २०२१ और २०२२ के बीच अब तक ५६० यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर चुकी है। इससे पहले २५ अप्रैल को १६ यूट्यूब चैनल बैन किए थे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय इससे पहले भी यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने की कार्रवाई कर चुका है। अप्रैल में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने को लेकर १६ यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया था। इनमें १० चैनल भारतीय और ६ पाकिस्तान आधारित यूट्यूब चैनल थे। आईटी नियम, २०२१ के तहत इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन्हें ब्लॉक किया गया था। मंत्रालय का कहना है कि ये सभी चैनल भारत में दहशत पैदा करने, सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए झूठी, असत्यापित जानकारी फैला रहे थे, जबकि हकीकत ये है कि ये चैनल भाजपा सरकार के खिलाफ खबरें चलाते थे, जिसे लेकर भाजपा सरकार की बहुत किरकिरी भी होती थी। ब्लॉक किए गए यूट्यूब समाचार चैनलों की दर्शकों की संख्या ६८ करोड़ से अधिक थी।

माहिम बीच पर कूड़े का अम्बार ...

दूर-दूर तक फैला है हजारों किलो कूड़ा

मुंबई : लोग जानते-बूझते हुए भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आ रहे हैं. पेड़ काटने से लेकर गगनचुंबी इमारते बनाना और पहाड़ों व समुद्रो में कूड़ा कचरा फेंकना लगातार जारी है. ये हाल तब है जब समुद्र में कचरे फेंकने के दुष्परिणामों को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा चुके हैं लेकिन लोग ने जैसे आंखे मूंद ली हैं. फिलहाल सोशल मीडिया पर मुंबई के समुद्र का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें समुद्र के किनारे पर काफी कचरा नजर आ रहा है. इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति ने लोगों को एहसास कराया है कि समुद्र में लोग द्वारा कितना कचरा फेंका जा रहा है.

बता दें कि एक मुंबई मैटर्स नाम के पेज ने ट्विटर पर मुंबई के माहिम बीच का

वीडियो शेयर किया है. वीडियो शेयर करने के साथ ही व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए लिखा गया है, ''मुंबई में समुद्र बीच अब खुल गए हैं. नागरिक माहिम समुद्र तट पर अरब सागर से मिले ''रिटर्न गिफ्ट'' देखने के लिए आते हैं ...'' गौरतलब है कि माहिम समुद्र बीच पर चारो तरफ फैला कूड़ा साफ बयां कर रहा है कि लोग कितना लापरवाह है और समुद्र को भी उन्होंने डंपयार्ड बना दिया है. यहां घूमने आने वाले लोग तमाम जागरूकता अभियान की अनदेखी करते हुए समुद्र में ही कूड़ा फेंक देते हैं. बता दें कि कोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मुंबई के माहिम बीच के इस वीडियो को अब तक 95 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

इधर वीडियो वायरल होते ही बीएमसी भी एक्शन मोड़ में आ गई और इस पर रिएक्शन देते हुए कई फोटो भी शेयर कर दिए. बीएमसी द्वारा शेयर किए गए फोटो में ये बताने की कोशिश की गई है कि निगम द्वारा लगातार समुद्र तट पर सफाई कार्य किया जाता रहा है. बहराहल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो काफी परेशान कर देने वाला है. जो लोग ये सोचते हैं इतने बड़े समुद्र में कूड़ा करकट फेंकने से कुछ नहीं होगा उनके लिए ये वीडियो एक झन्नाटेदार तमाचा है ताकि वे जागे और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से पहले सौ बार सोचें. बता दें कि इस वीडियो ने नेटिजन्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

संपादकीय / लेख

बच्चों की रचनात्मकता!

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

वो सारे नौनिहाल अपनी बालसुलभ ऊर्जा के साथ स्कूल बस स्टॉप पर खड़े थे। लेकिन कुछ झुके और बुझे-बुझे। आखिर वो पीठ पर लदा स्कूल बस्ता उनके बचपन को छीनने पर जो लगा था। माता-पिता भी परेशान थे, लेकिन आज कहीं न कहीं इस प्रतियोगी दौर में वे भी इस भारी बस्ते को प्रतियोगिता का हिस्सा मान बैठे हैं। अब जरा हम समझें कि इसको लेकर नियम क्या कहते हैं? नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूल बैग का वजन बच्चे के शरीर के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चे का वजन 25 किलो है तो उसके स्कूल बैग का भार 2.5 किलो होना चाहिए। प्रकाशकों द्वारा हर किताब का भार भी मुद्रित होना चाहिए। यह भी कि नर्सरी से कक्षा दो तक के छात्रों को कोई होमवर्क नहीं दिया जा सकता। कक्षा तीन से चार तक के छात्रों को प्रति सप्ताह केवल दो घंटे का होमवर्क दे सकते हैं। मिडिल स्कूल यानी 6वीं से 8वीं के छात्रों को रोजाना अधिकतम एक घंटा और हफ्ते में 5 से 6 घंटे होमवर्क दिया जा सकता है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक छात्रों को रोज अधिकतम 2 घंटे और प्रति सप्ताह 10 से 12 घंटे होमवर्क दिया जाना चाहिए। चेन्नई में प्राथमिक स्कूल के बच्चों के बीच स्कूल बैग और मस्कुलोस्केलेटल दर्द के संबंध को लेकर जानकीरमन बालामुरुगन का अध्ययन काफी महत्वपूर्ण है। यह माना गया कि भारी स्कूल बैग और अनुचित तरीके से ले जाने से बच्चों को मस्कुलोस्केलेटल समस्याओं का खतरा हो सकता है और शारीरिक मुद्रा बदल सकती है। अध्ययन में प्रत्येक छात्र के शरीर के वजन व स्कूल बैग के वजन को मापा गया। स्कूल बैग के वजन के प्रतिशत और बच्चों में मस्कुलोस्केलेटल दर्द की उपस्थिति के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध पाया गया। भारी स्कूल बैग बच्चों के विकास में बाधा डालते हैं और उनकी रचनात्मकता को प्रभावित करते हैं, साथ ही उनके स्कूल जाने के उत्साह को भी कम कर देते हैं। स्कूलों में डिजिटल माध्यम से शिक्षा का उपयोग तो शुरू हो ही गया है। ऐसा क्यों न करें कि किसी भी बच्चे को कोई पुस्तक लाने की जरूरत ही न रहे। शिक्षक उन्हें सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाएं और बच्चे कॉपी में नोट करते जाएं। हाइब्रिड मोड में शिक्षा दी जाए तो ज्यादा अच्छा है।

पश्चिम में बच्चों के पास स्कूल में लॉकर होते हैं, जिससे स्कूल ले जाने वाली पुस्तकों की संख्या कम हो जाती है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए सीखने को और अधिक मनोरंजक बनाने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार ने सप्ताह में एक दिन 'नो बैग डे' के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस एक दिन कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को तनावमुक्त समय देने और उन्हें मजेदार तरीके से अध्ययन करने पर जोर दिया जाएगा। अगर हमें बच्चों की मुस्कान बचानी है और नए भारत का निर्माण करना है तो शिक्षा को संवेदना से जोड़ना होगा ना कि सिर्फ स्कूल फीस से। स्कूल की सजगता और संवेदना बच्चों के बैग के वजन पर निगरानी और वजन कम करने की कवायद का हिस्सा हो। हमें बच्चों को सुनना भी चाहिए। आज भी बच्चे तमाम परेशानियों के बावजूद और भारी बैग लिए झुके कंधों के साथ भी अपने माता पिता के पास हंसते नजर आते हैं।

यह और बात है कि ऊंघते अनमने मध्य वर्ग के लिए बच्चे तो अब परीक्षा के अंक हो गए हैं। ऐसे में कौन समझे कि उनके कंधे और शरीर पर इस स्कूल बस्ते का क्या प्रभाव हो रहा होगा।

editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

आदित्य ठाकरे ने किया कुर्ला निर्वाचन क्षेत्र का दौरा

मुंबई : आम व्यक्तियों को असामान्य ताकत देने की शिवसेना की पहचान आगे भी कायम रहेगी, यह कहते हुए फिर से एक बार शिवसेना को खड़ी करें और बागियों को दिखा दें, ऐसा आ''ान शिवसेना नेता, युवासेनाप्रमुख व विधायक आदित्य ठाकरे ने कल शिवसैनिकों से किया। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अगली बार के विधायक इसी भीड़ में बैठे हैं।

आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को बागी विधायक मंगेश कुडालकर के कुर्ला निर्वाचन क्षेत्र में स्थित नेहरू नगर के शाखा क्रमांक-१६९ का दौरा करते हुए जनसभा ली। इस दौरान शिवसैनिकों को संबोधित करते समय अगला विधायक इसी भीड़ से होगा, ऐसी गर्जना करते हुए आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों को सीधे चुनौती दी है। बागियों से कह रहा हूं, जिन्हें आना है उनके लिए दरवाजा खुला है अन्यथा इस्तीफा देकर चुनाव का सामना करो और जीतकर दिखाओ, ऐसी खुली चुनौती भी आदित्य ठाकरे ने दी।

बीते दो-ढाई सालों में राज्य में राजनीति का समाजीकरण हो गया है। विश्व ने इसे नोटिस भी किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने परिवार के मुखिया के तौर पर आगे आ रहे थे। शिवसेना का मुख्यमंत्री था, पक्षप्रमुख ही मुख्यमंत्री थे, फिर इसमें गलत क्या चल रहा था? यह सवाल आदित्य ठाकरे ने उठाया था।

ईडी ने संजय राउत को फिर तलब किया, बुधवार को होगी पूछताछ...

मुंबईः ईडी ने एक बार फिर शिवसेना सांसद संजय राउत को तलब किया है. उन्हें कल पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया है। ईडी इससे पहले रौता से पूछताछ कर चुकी है। संजय राउत को ईडी के मुंबई कार्यालय ने मंगलवार को तलब किया था और उन्हें कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है. यह समन उन्हें मेल घोटाला मामले में जारी किया गया है। राउत से पहले भी दो बार पूछताछ हो चुकी है। इस मामले में ईडी ने आज संजय राउत के करीबी सहयोगियों सुजीत पाटकर और स्वप्ना पाटकर से करीब छह घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया.

मनपा का कमाल...मौसमी बीमारियां हुई बेहाल!

मुंबई : मुंबई में भले ही मौसमी बीमारियों की रफ्तार बढ़ गई हो लेकिन मनपा के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बरती जा रही सजगता के चलते भारी बारिश के बावजूद मौमसी बीमारियां बेहाल हो गई हैं। आलम यह है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों से ऐसी बीमारियों की रफ्तार न केवल धीमी पड़ गई है, बल्कि इस साल एक भी रोगी की जान भी नहीं ली है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते १७ दिनों में मलेरिया, गैस्ट्रो और डेंगू के महज ६१६ रोगी मिले हैं। फिलहाल मनपा की तरफ से इन बीमारियों की रोकथाम के लिए निवारक और एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस साल एक जनवरी से १७ जुलाई के बीच मुंबई में मलेरिया के १,४८६, डेंगू के १५६, लेप्टो के ४६, गैस्ट्रो के ३,२४६, हेपेटाइटस के २९१, चिकनगुनिया के ५ और एच१ एन के १५ मामले सामने आए। सबसे अच्छी बात यह है कि मौसमी बीमारियों से इस साल अभी तक किसी की भी मौत नहीं हुई है।

मच्छरों का किया जा रहा खात्मा

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बारिश और जलवायु परिवर्तन के चलते मौसमी बीमारियों के बढ़ने की संभावना अधिक होती है। ऐसे में डेंगू मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग नागरिकों से आ''ान किया है कि परिसर और आस-पास के क्षेत्रों को साफ रखने, टिन, थमाकौल बॉक्स, नारियल के खोल, टायर, अप्रयुक्त वस्तुओं आदि जैसी वस्तुओं को साफ रखकर मच्छरों के लार्वा प्रजनन को रोकें ।

उठाए जा रहे एहतियाती कदम

मुंबई में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए मनपा के स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती कदम उठाए हैं। मनपा ने लोगों से अपील की है कि जिस तरह से कोरोना को हराने का प्रयास किया गया था, उसी तरह इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की सलाह दी गई है।

लेप्टो पर लगेगा लगाम

बारिश में लेप्टो के प्रसार की संभावना अधिक होती है। ऐसे में मनपा स्वास्थ्य विभाग लेप्टो पर लगाम लागने में जुट गया है। मनपा की कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी मंगला गोमारे के अनुसार लेप्टो की रोकथाम के लिए ७,७८,७०९ घरों का सर्वेक्षण किया गया। इस बीच वयस्कों में डॉक्सी कैप्सूल के ९५,२१८ और बच्चों में एजिंथ्रोमायसिम के २३३ खुराक बांटी गई।

नागपुर में शख्स ने पत्नी-बेटे के साथ कार में लगाई आग

आर्थिक तंगी से था परेशान...!

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के नागपुर से एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने पत्नी और बेटे के साथ एक कार में खुद को आग लगा ली। घटना में शख्स की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बेटा बाल-बाल बच पाए। पुलिस ने बताया कि उक्त शख्स आर्थिक तंगी से परेशान था, इसी वजह से उसने यह खौफनाक कदम उठाया।

मां-बेटा गंभीर रूप से झुलस गए

पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि घटना बेलतरोड़ी थाना क्षेत्र के खपरी पुनर्वसन इलाके में दोपहर में हुई। मृतक की पहचान जैताला निवासी रामराज गोपालकृष्ण भट (58) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी संगीता भट (55) और बेटा नंदन (30) गंभीर रूप से झुलस गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

शख्स के असली मकसद से थे अनजान पत्नी और बेटा

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि 58 वर्षीय व्यक्ति के घर से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है जिसमें उसने कथित तौर पर कहा है कि वह वित्तीय संकट के कारण अपना जीवन समाप्त कर रहा है। पुलिस ने कहा कि रामराज भट ने अपनी पत्नी और बेटे को उसके असली मकसद का पता नहीं था। उसने एक होटल में दोपहर के भोजन के लिए जाने के बहाने कार में बैठाया।

अचानक डाला पेट्रोल और लगा दी आग

खपरी पुनर्वसन पहुंचने के बाद रामराज ने अचानक अपनी, पत्नी और बेटे पर पेट्रोल डाल लिया। इससे पहले कि मां-बेटा कुछ समझ पाते, उस व्यक्ति ने खुद को आग लगा ली और दोनों को आग लगा दी। पुलिस ने कहा कि मां-बेटा ने जल्दी से कार के दरवाजे खोले और किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन रामराज भट की वाहन में जलकर मौत हो गई।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : गुरुवार 21 जुलाई 2022

शिवसेना बनाम शिवसेना की कानूनी जंग में SC ने MLAs की अयोग्यता पर फैसला रोका

दोनों पक्षों को नोटिस किया जारी... !

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र मामले पर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की गई. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमना जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच द्वारा की गई. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अब एक अगस्त को सुनवाई होगी. साथ ही कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर हलफनामा दायर करने को भी कहा है. इतना ही नहीं महाराष्ट्र मामले में पांच जजों के संविधान पीठ का गठन भी हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी ओर इशारा किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई संवैधानिक मुद्दे हैं. जिन पर बड़ी बेंच के गठन की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने पक्षों को अगले बुधवार तक संवैधानिक सवाल दाखिल करने को कहा. एक अगस्त को अब सुनवाई होगी. तब तक अयोग्यता पर कार्यवाही नहीं होगी.

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले में बहस की शुरूआत करते हुए उद्धव ठाकरे का पक्षा रखा. उन्होंने कहा कि अगर इसकी इजाजत दी गई तो देश में किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है. सिब्बल ने कहा कि अगर इस तरह चुनी हुई सरकार पलटी गई तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा. इस तरह के परंपरा की शुरूआत किसी भी तरह से अच्छी नहीं हैं न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश में कही भी. उद्धव शिवसेना ग्रुप के विधायकों को कोई संरक्षण नहीं है.

कोर्ट के सामने सिब्बल ने कहा कि राज्यपाल ने शिंदे को शपथ दिलाई जबकि वो जानते थे कि उनकी अयोग्यता का मामला अभी स्पीकर के समक्ष लंबित है. पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया गया है. ये कानूनों का उल्लंघन है. उन्होंने स्वेच्छा से खुद को पार्टी से अलग कर लिया. व्हिप के खिलाफ मतदान किया. उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए. राज्यपाल को उन्हें शपथ लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी. दलबदल करने वाले विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से डिप्टी स्पीकर को कैसे रोका जा सकता है. कैसे फिर दूसरी सरकार बनाने की अनुमति दी जा सकती है.

सिब्बल ने आगे कहा कि हर दिन की देरी लोकतंत्र में शासन प्रणाली के साथ खिलवाड़ करेगी. एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला है और वह कहता है कि एक भी दिन के लिए नाजायज सरकार नहीं रहनी चाहिए. सिर्फ कानूनी तौर पर बनी सरकार रहे. वरना दसवीं अनुसूची के कानून की जरुरत क्या है. जिस कानून का काम दलबदल को रोकने के लिए बनाया गया था, उसी कानून के सहारे दल बदल को बढ़ावा दिया जा रहा है.

तत्कालीन डिप्टी स्पीकर का रखा पक्ष

वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्कालीन डिप्टी स्पीकर (उद्धव गुट) की ओर से बहस शुरू करते हुए कहा कि एक अनधिकृत मेल से डिप्टी स्पीकर को एक ईमेल भेजा गया था. इसमें डिप्टी स्पीकर पर अविश्वास की बात कही. ऐसे मेल को कैसे वैध माना जा सकता है? आप इस ईमेल के आधार पर कैसे कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का स्टेटस अब मान्य नहीं है. 10 से अधिक फैसले हैं, जहां इसे एक संवैधानिक पाप कहा है. गुवाहाटी जाने से एक दिन पहले इन लोगों ने उपसभापति को यह कहते हुए एक मेल भेजा कि हमें आप पर भरोसा नहीं है. विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में जब डिप्टी स्पीकर के हाथ बंधे हुए थे, तो फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए था. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दुरुपयोग करना चाहते हैं.

सिंघवी ने कहा कि अभी तक शिंदे कैम्प किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुआ है. लेकिन फिर भी उन्हें अयोगय घोषित नहीं किया हैं. कर्नाटक मामले में रउ ने पूरी रात मुद्दों को सुना. इस मामले में भी अदालत के पास चीजों को पलटने का अधिकार है. इस केस में नैतिक, कानूनी और सदाचार का मुद्दा शामिल. सिंघवी ने कहा की क्लॉज 4 के तहत संवैधानिक जरूरत है कि उन्हें मर्जर करना होता है. इसमें केवल संवैधानिकता कोर्ट तय कर सकता है. हमारे अर्जी पर स्पीकर ने कोई करवाई नहीं की. बल्कि बहुमत परीक्षण के बाद उद्धव ठाकरे कैम्प के विधायकों को नोटिस जारी कर दिया गया. इस मामले को कोर्ट स्पीकर के पास न भेजे. कोर्ट ही इस मामले को तय करे. सिंघवी ने कहा कि यह दसवीं अनुसूची के साथ मजाक हो रहा है. अदालत चुनाव प्रक्रियाकी शुद्धता सुनिश्चित करे.

एकनाथ शिंदे का रखा पक्ष

एकनाथ शिंदे की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए और उन्होंने कहा कि अयोग्यता के नियम शिंदे मामले में लागू नहीं होता है. क्योंकि अगर किसी पार्टी में दो धड़े होते है और जिसके पास ज्यादा संख्या होती है वो कहता है कि मैं अब नेता हूं और स्पीकर मानता है तो ये अयोग्यता में कैसे आएगा. आंतरिक पार्टी लोकतंत्र गला घोंटा जा रहा है. यदि पार्टी में असंतोष है और पार्टी में किसी अन्य व्यक्ति को नेता के रूप में चुना जाता है. ऐसा सभी लोकतंत्रों में होता है. ऐसे देश हैं, जहां पीएम को भी हटना पड़ता है. इन विधायकों ने सदन में बहुमत साबित कर दिया तो वह दलबदल नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने साल्वे से कहा कि हम आपको सुनेंगे, लेकिन हमारे मन में कुछ सवाल हैं. Chief Justice ने कहा कि यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला है. इसलिए मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि लगे कि हम एक पक्ष की ओर झुक रहे हैं. लेकिन अगर ये मान लें की पार्टी में कोई विभाजन नहीं है तो परिणाम क्या होंगे?

साल्वे ने कहा कि इसमें अयोग्यता का मामला नहीं है. एक आदमी जो अपने समर्थन में 20 लोग भी नहीं कर सकता वो कोर्ट से राहत की उम्मीद कर रहा है. मुझे ये अधिकार है कि मैं अपनी पार्टी में आवाज उठाऊ. पार्टी में लक्ष्मण रेखा क्रॉस किए हुए अपनी बात को उठाना कही से भी अयोग्यता के दायरे में नहीं आएगा.

बारिश में मुंबई की सड़कों पर भरा पानी, नालों की नहीं हुई सफाई,

बीजेपी विधायक ने BMC कमिश्नर से की शिकायत

मुंबई : मुंबई में हर साल बारिश के मौसम में कहीं ना कहीं जल जमाव होता है. सड़कों पर या फिर गलियों में पानी जमने की वजह से मुंबई वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसी संदर्भ में आज बीजेपी के विधायक योगेश सागर ने मुंबई के बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल से शिकायत की है. उन्होंने बीएमसी के तमाम ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. विधायक ने यह भी दावा किया है कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद इस साल मानसून से पहले नालों की 10 फीसदी भी सफाई नहीं हुई है.

बीजेपी विधायक योगेश सागर ने 20 जुलाई को इटउ कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा कि नालों की सफाई नहीं होने की वजह से जलजमाव

होता है और नागरिकों को आने जाने में असुविधा होती है.

बीजेपी विधायक योगेश सागर ने आगे कहा कि मुंबई में पिछले आठ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और नाले साफ नहीं होने की वजह से पानी का निकास नहीं होता है. विधायक ने आरोप लगाया है कि बड़े नाले के लिए 83.9 करोड़ रुपये और छोटे नाले के लिए 102.35 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद 10 प्रतिशत सफाई भी नहीं हुई है. बीजेपी विधायक ने मांग करते हुए कहा है कि ठेकेदारों ने जो साफ सफाई की है, वो सिर्फ.कागज पर दिखाई देता है. जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. विधायक ने इटउ कमिश्नर इकबाल चहल से मांग की है कि ठेकेदारों के काम जो पेपर पर हैं, उसकी जांच हो और जब तक जांच पूरी नहीं होती है, उन्हें उनके पैसों का भुगतान ना करें.

बीएमसी ने 30 मई को दावा किया था कि बरसात से पहले 99 फीसदी नालों की सफाई का काम पूरा कर लिया गया है. बीएमसी ने कहा था कि छोटे नाले और पूर्वी उपनगरों से गाद निकालने का काम पूरी तरह से पूरा हो गया है, जबकि द्वीप शहर, पश्चिमी उपनगर और मीठी नदी पर काम एक दो दिनों में पूरा हो जाएगा.

हाई-प्रोफाइल ठग, ट्रांसपोर्टर्स थे टारगेट!

'यादगार' होटल में फरमा रहा था आराम, पुलिस ने धर दबोचा...

मुंबई : राज्य में ठगी की वारदात को अंजाम देनेवाले हाई-प्रोफाइल ठग को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह शातिर ठग सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को टारगेट करता था। ठगी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी यादगार होटल में आराम फरमाता था। हालांकि इसकी भनक मुंबई क्राइम ब्रांच को लग गई और उसे धर-दबोचा।

जोन-१२ क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विलास भोसले ने बताया कि शातिर आरोपी सातारा जिले का निवासी है। शातिर आरोपी ओला उबर और ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर का काम करनेवाले लोगों से पहले दोस्ती करता था। इसके बाद उन्हें राज्य के महावितरण कंपनी, ओएनजीसी, राज्य उत्पादक शुल्क जैसी कंपनी में सरकारी नौकरी

लगाने का झांसा देता था। साथ ही पीड़ितों को भरोसा दिलाने के लिए फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर, आईकार्ड दिखता था। जब लोग इसके जाल में फंस जाते तो उनसे लाखों रुपए लेकर फरार हो जाता था, जिसकी जांच मुंबई पुलिस सहित क्राइम ब्रांच कर रही थी।

पुलिस के मुताबिक ३७ वर्षीय आरोपी की तलाश में शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की जांच पुलिस कर रही थी। इसके अलावा राज्य के मुखबिरों का एक जाल बिछाया गया था। मुखबिरों को आरोपी की फोटो सकुर्लेट की गई थी। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को मुखबिरों ने बताया कि आरोपी एक घटना को अंजाम देकर ग्रांट रोड के 'यादगार' होटल में आराम फरमा रहा है। इसके बाद पुलिस ने छापामारी करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से अपॉइंटमेंट लेटर, आईकार्ड, मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र सहित अन्य कागजात बरामद किए गए हैं।

पुलिस के मुताबिक आरोपी मीठी-मीठी बातें करके पीड़ितों के परिवार के करीब पहुंचा जाता था। इसके बाद उन्हें भी सरकारी नौकरी दिलवाने का ख्वाब दिखाकर उनका शिकार करता था। आरोपी के खिलाफ आरे, दादर, मरीन ड्राइव, शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज है। इसके अलावा सोलापुर, संभाजीनगर, कोल्हापुर, रत्नागिरी, बुलढाणा, सातारा, भंडारा आदि स्थानों के पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज हैं। फिलहाल मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही हैं।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : गुरुवार 21 जुलाई 2022

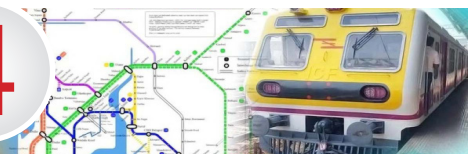

मुंबई के अक्सा बीच की लॉज पर तीन धोखेबाजों ने की थी फर्जी छापेमारी !

मुंबई : मुंबई से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल यहां एक पुरुष और दो महिलाओं ने एंटी करप्शन के अधिकारी बनकर पिछले हफ्ते अक्सा समुद्र तट पर एक लॉज पर छापा मारा और वहां रहने वाले युवा जोड़ों से अपने माता-पिता को सूचित करने की धमकी देकर पैसे की मांग की थी. हालांकि, लॉज मालिक को शक हुआ और उसने मालवानी पुलिस को सूचित कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फर्जी अधिकारी बनकर आए तीनों आरोपियों की जबरन वसूली की योजना को विफल कर दिया.

कप्लस से की थी इतने रुपये की डिमांड

दोनों आरोपी महिला हो गई थीं फरार

पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान मनोज कुमार रामसय्या सिंह, अनीता वर्मा और काजिया खान के रूप में हुई है, वे एनजीओ एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं चूंकि घटना शाम को हुई थी, पुलिस केवल 14 जुलाई को युवक को ही गिरफ्तार कर सकी थी और खान और वर्मा को जाने दिया गया था लेकिन दोनों महिलाओं को अगले दिन थाने में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था हालांकि वे फरार हो गई थी.

आरोपियों ने कपल्स के परिजनो को सूचना देने की धमकी दी थी

पुलिस बताया कि मनोज कुमार रामसय्या सिंह और अनिता वर्मा पुणे के रहने वाले हैं, जबकि खान मलाड के मालवानी में आजमी नगर में रहती है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लॉज में फर्जी छापेमारी के दौरान तीनों ने मालिकों के साथ ग्राहकों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया. इसके बाद उन्होंने कपल्स को उनके कमरे से बाहर निकाल दिया, उनके माता-पिता के फोन नंबर मांगे और उन्हें सूचित करने की धमकी दी थी.

आरोपियों ने सभी कपल्स से 5 हजार रुपये की डिमांड की थी

इसके बाद उन्होंने डरे हुए कपल्स और लॉज मालिक से प्रत्येक से 5,000 रुपये की डिमांड की थी. हालांकि, वह उनके जाल में नहीं फंसे थे. दरअसल लॉज मालिक ने पुलिस को खबर कर दी थी. जिसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर शेखर भालेराव के नेतृत्व में असिस्टेंट इंस्पेक्टर नीलेश सालुंखे और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर तीनों को हिरासत में ले लिया. सिंह फिलहाल पुलिस हिरासत में है. पुलिस को संदेह है कि यह उनका जबरन वसूली का पहला प्रयास नहीं था.

मुंबई पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार

NSE ने मामले की जांच की तेज

मुंबई : बाजार के निवेशकों के हितों को देखते हुए जी बिजनेस ने एक मुहिम की शुरूआत की. नाम था 'ऑपरेशन डीमैट डाका'. ये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन शो था, जिसके जरिए जी बिजनेस अपने दर्शकों/पाठकों को डीमैट के जरिए हो रहे फ्रॉड के बारे में बताया. अब इस ऑपरेशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. ऑपरेशन डीमैट डाका का बड़ा असर देखने को मिला है. मुंबई पुलिस ने इस स्टिंग ऑपरेशन के तहत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. जिसमें 3 आरोपी मुंबई और 2 आरोपी अहमदाबाद से गिरफ्तार हुए.

जी बिजनेस की ओर से ऑपरेशन डीमैट डाका शो चलाया गया और इस शो के जरिए डीमैट के जरिए हो रहे अलग-अलग फ्रॉड्स के बारे में जानकारी दी गई. वहीं आज ब्रोकर के साथ निजी कर्मचारियों की बैठक है और एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इस मामले की जांच तेज की है. दरअसल तेजी से लोकप्रिय हो रहे शेयर बाजार में डकैतों के निशाने पर है आपका डीमैट अकाउंट. जहां बिना किसी खून-खराबा और हथियार का इस्तेमाल किए ये लूटेरे आपकी जीवन भर की कमाई साफ कर देते हैं...और टेक्नॉलॉजी के जमाने में सिर्फ एक बटन दबाकर आपके डीमैट खाते को हैक कर लेते हैं और पलक झपकते ही आपके पोर्टफोलियो के सारे शेयर बेचकर उसकी जगह आपके खाते को पेनी स्टॉक, छोटे शेयर या इलिक्विड स्टॉक से भर देते हैं.

महाराष्ट्र में मंत्री बनवाने का झांसा देकर ठगी का प्रयास...!

तीन भाजपा विधायकों से मांगे 100 करोड़

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार बने 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। हैरानी तो तब हुई जब एक ठग गिरोह ने मंत्री बनाने के लिए विधायकों को ठगने का प्रयास किया। गिरोह ने तीन भाजपा विधायकों से मंत्री बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि मांगी थी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने विधायकों से ठगी के प्रयास में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम हैं रियाज शेख, योगेश कुलकर्णी, सागर सांगवाई और जफर उस्मानी। चारों आरोपियों को 26 जुलाई तक क्राइम ब्रांच की

हिरासत में सौंपा गया है। एफआईआर के मुताबिक, विधायक से शिंदे मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनवाने के बदले 100 करोड़ रुपये की मांग की गई थी।

ठग रियाज शेख ने फोन कर यह कहा था

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार ठग रियाज शेख ने 17 जुलाई को दोपहर 12.12 बजे एक विधायक के सचिव को फोन किया कि दिल्ली से आया हूं, मेरी आज विधायक साहब से 4 बजे मीटिंग है, लेकिन विधायक फोन ही नहीं उठा रहे हैं। इस पर सचिव ने रियाज का मैसेज विधायक को भेज दिया, लेकिन विधायक ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। रियाज ने शाम को 4.06 बजे फिर सचिव को फोन किया और कहा कि 4 बजे वाली मीटिंग के लिए विधायक का अभी भी इंतजार कर रहा हूं। सचिव के जरिए फिर विधायक को मैसेज भेजा गया, लेकिन विधायक की तरफ से फिर कोई जवाब नहीं आया। उसी दिन विधायक की शाम साढ़े चार बजे दक्षिण मुंबई के सात सितारा होटल में अपने सचिव से मीटिंग पहले से फिक्स थी, क्योंकि सचिव एक दिन पहले यानी 16 जुलाई को रात 9 बजे विधायक से आकाशवाणी भवन के पास विधायक निवास में मिल चुका था।

इसके बाद रियाज को विधायक ने 18 जुलाई को दोपहर करीब एक बजे नरीमन पाइंट इलाके में बुलाया और मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन सेल को भी यह सूचना दे दी गई।

90 करोड़ में सौदा तय हुआ, एडवांस मांगे 18 करोड़

सचिव ने एक होटल में विधायक से मुलाकात के दौरान उनसे रियाज शेख के बार-बार फोन आने की बात कही, तब विधायक ने भी सचिव को बताया कि उसे 12 जुलाई को रियाज शेख का फोन आया था और कहा था कि आपको कैबिनट मंत्री बनवा देंगे, लेकिन 100 करोड़ रुपये लेंगे। विधायक ने तब रियाज को कोई महत्व नहीं दिया था, लेकिन 17 जुलाई को शाम साढ़े चार बजे सचिव से मुलाकात के बाद विधायक ने सचिव के जरिए रियाज को शाम को सवा पांच बजे संबंधित होटल में मिलने बुलाया। रियाज और विधायक की वहां लंबी मीटिंग हुई। रियाज ने सौदा 90 करोड़ रुपये में फिक्स किया, लेकिन एडवांस में 18 करोड़ रुपये मांगे। इसके बाद विधायक ने रियाज से अगले दिन तक रुकने को कहा और यह बात अपने निजी सचिव को बताई।

सीएम एकनाथ शिंदे की चुनाव आयोग से मांग

'हमें मिले असली शिवसेना की मान्यता'

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को लगातार झटके दे रहे हैं. हालिया मामला सीएम शिंदे के चुनाव आयोग को शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता देने की मांग का है. चुनाव आयोग के सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की है. सूत्रों के मुताबिक मंगलवार 19 जुलाई देर शाम शिंदे गुट के सांसदों की तरफ से चुनाव आयोग को एक पत्र मिला है. इसमें शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता देने की मांग की गई है. हालांकि इस पर फैसला करने के लिए ईसी राजनीतिक दल की मान्यता से जुड़ी प्रक्रिया के तहत दोनों दलों को समान अवसर देगा.

बीएमसी चुनाव में धुनष-तीर किसका?

शिंदे के इस कदम से शिवसेना के उद्धव धड़े के ''धनुष और तीर-के चिन्ह के बगैर निर्णायक बीएमसी चुनाव लड़ने की संभावना बढ़ती जा रही है. गौरतलब है कि ये प्रतीक शिवसेना का पर्याय बन गया है. एक सूत्र के मुताबिक चुनाव आयोग को लिखे पत्र में शिंदे गुट ने शिवसेना के 12 सांसदों के समर्थन का जिक्र तो किया है, लेकिन अधिक विवरण उपलब्ध नहीं दिया है. अटकलें हैं कि शिंदे गुट

अपने आरक्षित पार्टी चिह्न 'धनुष और तीर' का इस्तेमाल करने के अधिकार के साथ 'असली' शिवसेना के रूप में पहचाने जाने की मांग कर रहा है. उद्धव धड़े ने पहले ही चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि पार्टी के नाम और प्रतीक के दावे के मामले में उनके विचारों को सुना जाए.

चुनाव आयोग का क्या होगा कदम?

इस तरह के मामले में पहले लिए गए फैसलों को चुनाव आयोग मिसालों के तौर पर ले सकता है. आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निहित शक्तियों के आधार पर प्रतीकों पर सभी विवादों को सुनता है. इसमें संगठनात्मक और विधायी विंग में बहुमत के समर्थन के आधार पर फैसला लिया जाता है. इस तरह के विवादों में सुप्रीम कोर्ट के सादिक अली बनाम चुनाव आयोग केस में दिए फैसले को नजीर की तरह लिया जाता है.

शिंदे गुट ने कहा - दो तिहाई सांसदों का है समर्थन

गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे ग्रुप ने अपने साथ दो तिहाई से अधिक विधायक और शिवसेना के 19 में से 12 सांसद के समर्थन के आधार पर शिवसेना पर ये दावा ठोका है. इसी को आधार बनाकर शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है. चुनाव आयोग के सूत्रों ने पुष्टि की है कि शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट से मंगलवार शाम करीब 6 बजे एक पत्र मिला था. ये पत्र पार्टी के 19 सांसदों में से 12 के लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखने के कुछ ही घंटे बाद लिखा गया है. गौरतलब है कि 12 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को यह पत्र उनके सहयोगी राहुल शेवाले को उनके नेता और भावना गवली को मुख्य सचेतक की मान्यता देने को लेकर लिखा था.

इसके तहत ही यह फैसला लिया जाता है कि कौन वास्तविक पार्टी है और कौन पार्टी प्रतीक चिन्ह का असली हकदार है. चुनाव आयोग पार्टी संगठन और विधायी और संसद विंग में समर्थन के संबंध में गुटों के लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों के आधार पर बहुमत के समर्थन का मूल्यांकन करता है.

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैजल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नंबर 3-4, अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट, सोनावाला क्रॉस रोड नंबर 12, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई - 63 से छपवाकर रुम नंबर 15 रमजान बिन 17- सी, वंजावडी, माहिम (वेस्ट), मुंबई - 400016 से प्रकाशित किया . संपर्क कार्यालय 1 ए, ग्राउंड फ्लोर, साहिल मेन्शन, बालमिया लेन, माहिम (वेस्ट), मुंबई - 400016.
मोबाइल नंबर 9987775650 व्हाट्सएप नंबर 9987775650 ईमेल- editor@rokthoklekhaninews.com -किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मुंबई होगा!
www.rokthoklekaninews.com facebook@rokthoklekhani youtube@rokthoklekhani twitter@rokthoklekhani